# HRA AN UNIVA The Gazette of India

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 329 ] No. 329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 1998/भाद्र 5, 1920 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 1998/BHADRA 5, 1920

## वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

सा. का. नि. 531 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उम्स् नियम'' कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1998 है।

दर (प्रति भास)

- (2) ये 1 जुलाई, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. उक्त नियमों के नियम 4' के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

''4क. विशेष भता: (1) नियम 4 के उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट, 1 जुलाई 1996 से लागू वेतनमानों के अतिरिक्त, प्रत्येक विकास अधिकारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक एक विशेष भत्ता प्राप्त करेगा, अर्थात्:—

(1)

भूल वेतन की श्रेणी	विशेष भत्ते की
3125 रु. तक	70 रू.
3126 रु. से 4070 रु. <b>तक</b>	80 F.
4071 रु. से 4530 रु. तक	100 ₹.
4531 रु. से 5450 रु. तकः	115 <del>T</del> .
5451 रु. और उससे अधिक	135 ₹.

2308 GI/98

- (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विशेष भत्ता मूल बेतन के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा किन्तु उक्त नियमों के नियम 5 में निर्दिष्ट मंहगाई भत्ता, नियम 6 में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता, नियम 7 में निर्दिष्ट नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, नियम 8 में निर्दिष्ट भविष्य मिधि, नियम 9 में निर्दिष्ट उपदान, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेन्शन निगम, 1995 के अधीन पेंशन और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के नकदीकरण की गणमा के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाएगा।
  - 4ख (1) नियम 4क में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष साम्यापूर्ण राहत के रूप में बकाया प्रदान कर सकता है: परन्तु यह कि-
- (क) साम्यापूर्ण राहत रूप में 1 जुलाई, 1996 से प्रारंभ होने और 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसा संदाय, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय मिबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संदाय का आधा, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, संबंधित विकास अधिकारी के 31 जुलाई, 1998 के पश्चात् तुरन्त आरंभ होने वाले आकलन वर्ष के वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा: और
- (ख) साम्यापूर्ण राहत के रूप में 1 अप्रैल, 1997 से आरंभ होने और 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसा संदाय, भारतीय जीवन बीमा मिगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) मियम, 1989 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संदाय का अथवा इन नियमों के प्रयोजन के लिए, संबंधित विकास अधिकारी के 31 जुलाई, 1999 के पश्चात् तुरन्त आरंभ होने वाले आकलन वर्ष के वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा।

संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1998 से आरंभ वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित विशेष भत्ता, उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत आकलन वर्ष के वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा।''

> [फा. सं. 6(26)/बीमा III/97 (1)] सी. एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

# स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने निगम के विकास अधिकारियों को अतिरिक्त मजदूरी फायदा, 1-7-96 से देने का अनुमोदन कर दिया है। तदनुसार भारतीय जीवृत बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 में संशोधन किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से जीवन बीमा निगम के किसी विकास अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण :— मूल नियम सा.का.नि. सं. 1091 (अ) तारीख 17-9-1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् सा.का.नि. 962(अ) तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. सं. 871(अ) तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. सं. 968(अ) तारीख 7-11-1989, सा.का.नि. सं. 825(अ) तारीख 9-10-1990, सा.का.नि. सं. 55(अ) तारीख 21-1-1992, सा.का.नि. सं. 325(अ) तारीख 10-3-1992, सा.का.नि. सं. 54(अ) तारीख 2-2-1994, सा.का.नि. सं. 596 तारीख 30-6-1995, सा.का.नि. सं. 95(अ) तारीख 16-2-1996, और सा.का.नि. सं. 287(अ) तारीख 18-7-1996।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

# Insurance Division NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1998

G. S. R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of service) Rule, 1986 (hereinafter referred to as the "said rules", namely:—

### 1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1988.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 1996.
- 2. After rule 4 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:
- "4A. Special Allowance: (1) In addition to the scales of pay specified in sub-rule 1 of rule 4, with effect from the 1st day of July, 1996, every Development Officer shall receive a Special Allowance to the extent specified below, namely:—

Range of Basic pay	Rate of Special Allowance (per month)	
Upto Rs. 3125/-	Rr 70/-	
Rs. 3126/- to Rs4070/-	Rs. 80/-	
Rs. 4071/- to Rs. 4530/-	Rs. 100/-	
Rs. 4531/- to 5450/-	Rs. 115/-	
Rs. 5451/- and above	Rs. 135/-	

- (2) The special allowance, as specified in sub-rule (1) shall not be treated as part of the basic pay but shall count for the purpose of calculation of dearness Allowance referred to in rule 5, House rent Allowance referred to in rule 6, City Compensatory Allowance referred to in rule 7, Provident Fund referred to in rule 8, Gratuity referred to in rule 9 of the said Rules, Pension payable under Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995 and Encashment of Privilege Leave.
  - 4B (1) Notwithstanding anything contained in rule 4A, the Chairman may grant arrears by way of equitable relief: Provided that—
  - (a) such a payment by way of equitable relief for the period commencing on 1st July, 1996 and ending with 31st March, 1997, notwithstanding anything contained in Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of certain Terms and Conditions Service) Rules, 1989, one half of such a payable shall, for the purpose of those rules, form part of the annual remuneration of the Development Officers concerned in the appraisal year commencing immediately after the 31st July, 1998; and
  - (b) Such a payment by way of equitable relief for the period commencing on the 1st April, 1997 and ending with the 31st March, 1998, notwithstanding anything contained in Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of certain Terms and Conditions Service) Rules, 1989, one half of such a payment shall, for the purpose of these rules, form part of the annual remuneration of the Development Officers concerned in the appraisal year commencing immediately after the 31st July, 1999; and
  - (2) For the removal of doubts, it is clarified that the special allowance relating to the financial year commencing on the 1st April, 1998, shall form part of the annual remuneration of the revelant appraisal year in that financial year.".

[F. No. 6(26)/Ins. III/97-(i)]

C.S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government have accorded approval to release additional wage benefit to the Development Officers of the Corporation with effect from 1-7-1996. Accordingly, the Life Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions Service) Rules, 1986, have been amended.

It is certified that no Development Officer of Life Insurance Corporation of India likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Foot Note: The principal rules were published vide G.S.R. No 1091(E) dated 17-9-1986 and subsequently amended vide G.S.R. No. 962(E) dated 7-12-1987, G.S.R. No. 871(E) dated 22-8-1988, G.S.R. No. 968(E) dated 7-11-1989, G.S.R. No. 825(E) dated 9-10-1990, G.S.R. No. 55(E) dated 21-1-1992, G.S.R. No. 325(E) dated 10-3-1992, G.S.R. No. 54(E) dated 2-2-1994, G.S.R. No. 596(E) dated 30-6-1995, G.S.R. No. 95(E) dated 16-2-1996 and G.S.R. No. 287(E) dated 18-7-1996.